देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 15 अंक: 160 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

देहरादून, शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

विचार-प्रवाह...तीन तलाक, बड़ा रिफार्म

पेज थ्री

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 31.0° न्यूनतम 21.0°

37244.59 | 2 यूजीसी की नई पहल | 7 बिपाशा ने पूरे किये बॉलीवुड में 18 साल

संक्षिप्त समाचार

बदरीनाथ धाम पहुंचीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, किए बदरीविशाल के दर्शन

संवाददाता देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा ने बृहस्पतिवार को बदरीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बदरीविशाल के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। दोपहर 12.00 बजे वह सड़क मार्ग से बदरीनाथ धाम पहुंचीं।

मंदिर परिसर में उमा भारती का स्वागत उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बदरीनाथ के अपर मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, धर्माधिकारी भुवनचंद्र उनियाल और बोर्ड के अधिकारियों ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बुधवार 23 सितंबर से चमोली जिले के भ्रमण पर हैं।

जल्द दूसरे राज्यों में दौड़ती दिखाई देंगी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड सरकार अनलॉक के चौथे चरण में अब जल्द ही अंतरराज्यीय बस सेवाओं का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही है। यानी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें जल्द ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल व हरियाणा जैसे अन्य प्रदेशों में जा सकेंगी, जबकि इसी क्रम में पूर्व की तरह बाहरी राज्यों की बसें भी उत्तराखंड राज्य में आ सकेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पिछले 6 माह के अधिक समय से न तो उत्तराखंड परिवहन निगम बसें राज्य से बाहर जा पा रही थीं और न ही अन्य राज्यों की बसें राज्य में आ रही थीं।

पूर्व विधायक कृष्ण चंद्र पुनेठा का निधन

संवाददाता देहरादून। उत्तर प्रदेश के समय पिथौरागढ़ क्षेत्र से विधायक रहे भाजपा नेता कृष्ण चंद्र पुनेठा का निधन हो गया। उन्होंने अंतिम सांस लोहाघाट के फोर्ती स्थित निवास पर ली। वह लंबे समय से बीमार थे। कृष्ण चंद्र पुनेठा के ही फेसबुक अकाउंट से उनके पुत्र ने बीती रात करीब एक बजे उनके निधन की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है।

किसानों का डाटा बेस किया जाय तैयार

धान खरीद के लिए 10 लाख मी०टन का निर्धारित किया लक्ष्य, बनाये जायेंगे 242 क्रय केन्द्र

■मुख्यमंत्री ने की खरीफ खरीद सत्र 2020-21 की समीक्षा

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा गुरूवार को सचिवालय में खरीफ खरीद सत्र 2020-21 हेतु धान क्रय सम्बन्धी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष 242 धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से 10 लाख मी0टन धान क्रय के लक्ष्य पर सहमति व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में समय से सभी आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष इस वर्ष ए ग्रेड धान का मूल्य रूपये 1888 प्रति कुंतल तथा औसत धान का रूपये 1868 प्रति कुंतल निर्धारित किये जाने पर भी सहमति जतायी। उन्होंने आगामी 01 अक्टूबर से की जाने वाली धान क्रय के सम्बन्ध में सभी व्यवस्थायें ससमय सुनिश्चित करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी रह गई हो तो उसका संज्ञान लेकर उससे बेहतर व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाय। उन्होंने धान मूल्य का किसानों को अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग को आवश्यक धनराशि व्यवस्था करने के साथ ही प्रबन्ध निदेशक मण्डी को भी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। किसानो को बेहतर सुविधाये उपलब्ध हो इसके लिए किसानों का डाटा तैयार करने पर भी ध्यान देने के निर्देश भी उन्होंने दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान की खरीद तैयार किये गये ई खरीद साफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की जाय तथा किसानों की सुविधा के लिये उन्हें घर पर ही आनलाइन पंजीकरण कराने तथा टोकन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

सीएम त्रिवेंद्र बैठक लेते हुए।

सचिव खाद्य सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाये की जा रही है। धान के लिए बौरो की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि धान क्रय के लिए खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग,एनसीसीएफ एवं नैफैड एजेंसियां निर्धारित की गई है। कच्चा आढ़तियों के माध्यम से भी धान क्रय की व्यवस्था है जबकि खाद्य नागरिक आपूर्ति विपणन एवं आपूर्ति के साथ ही उत्तराखण्ड राज्य भण्डारण निगम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के स्तर पर भण्डारण की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष लगभग 2,50,000 हैक्टयर के माध्यम से धान की बुआई हुई थी, जिसके सापेक्ष 10 लाख मी0टन0 धान क्रय का लक्ष्य प्रस्तावित कि गया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत इस वर्ष किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्रों में वृद्धि की गई है। बैठक में सचिव वित्त श्रीमती सौजन्या, सचिव कृषि श्री हरबंश सिंह चुघ सहित खाद्य सहकारिता, मण्डी परिषद के अधिकारीगण तथा राइस मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

अल्मोड़ा के काभड़ी गांव में 91 कोरोना पॉजिटिव निकले

पूरे क्षेत्र में मंचा हडकंप, सभी ग्रामीणों का होगा कोरोना टेस्ट

संवाददाता

देहरादून। अल्मोड़ा के धौलादेवी के काभड़ी गांव में 91 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे गांव से जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के लिए रवाना हो गई है। हाल ही में गांव लौटे एक प्रवासी में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी और फिर हल्द्वानी में 19 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ऐहतिहातन गांव में लोगों के सैंपल लिए थे। बुधवार देर रात टेस्ट रिपोर्ट्स आईं जिनमें 91 लोगों के पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है। किसी एक स्थान से इतने सारे लोगों के कोरोना संक्रमित होने का यह पहला मामला है।

खास बात यह है कि गांव किसी भी व्यक्ति में कोरोना का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा है

स्वास्थ्यकर्मी जांच करते हुए।

यानी सभी ए-सिम्पटमैटिक हैं। 19 तारीख को गांव के प्रवासी की मौत के बाद अगर प्रशासन गांव के करीब 250 लोगों के टेस्ट नहीं करवाता तो शायद ही इतने लोगों के संक्रमित होने का पता चलता। ग्राम प्रधान की रिपोर्ट भी कोविड-19 पॉजिटिव आई है। इससे पहले बीते सोमवार को अल्मोड़ा में 90 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इनमें कोटयूड़घ गांव में 67 लोग संक्रमित मिले थे जो तब तक किसी गांव में एक साथ संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या थी। बुधवार को यह रिकॉर्ड काभड़ी गांव में टूटा है। सोमवार को 90 लोगों में से 6 जीबी पंत पर्यावरण संस्थान में, 9 भिकियासैंण विकासखण्ड में, 6 सल्ट विकासखण्ड में और 2 लमगड़ा विकासखण्ड में पॉजिटिव पाए गए थे।

राज्य सरकार की पिरुल नीति पर बैंकों का अड़ंगा

संवाददाता

देहरादून। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चीड़ पिरूल आधारित विद्युत उत्पादन और स्वरोजगार के उद्देश्य से पिरुल व अन्य प्रकार के बायो ऑयल से एमएसएमई के तहत पेरूल नीति दो साल से सरकार धरातल पर नहीं उतार पा रही है। जबकि उरेडा और अन्य सभी विभाग बड़ी दिलचस्पी के साथ इस नीति को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बैंकों इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। बैंक फाइलों को निरस्त कर उद्यमियों को मायूस कर रहे हैं। जिससे सरकार की इस बहुआयामी योजना को दो वर्ष से परवान नहीं चढ़ पा रही।

वर्ष 2018 की पेरूल नीति को स्वयं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लांच किया था और उरेडा विभाग को इस योजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी दी थी। यूपीसीएल के साथ भी बिजली खरीदने का अनुबंध भी हुआ था। राज्य भर मे प्रथम चरण में इक्कीस उद्यमियों को पेरुल से बिजली उत्पादन के

दिक्कतें

■दो वर्षो से परवान नहीं चढ़ पाई योजना
■बैंक फाइलों को निरस्त कर उद्यमियों को मायूस कर रहे हैं।

प्लांट लगाने के लिए शासन ने एम एस एम ई के तहत स्वीकृति दी थी। उद्यमियों ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर प्रशासनिक स्वीकृति भी ली और फाइलें वित्त पोषित के लिए बैंकों को भेजा। दो साल बीत गये मगर बैंकों ने अब तक केवल दो कुमांऊ और एक गढ़वाल से ही प्लांट उद्यमियों को वित्त पोषित किया है। और शेष अन्य लोगों की फाइलों पर अनावश्यक आपत्तियां लगाकर फाइलें वापस डीआईसी को भेज दी जिससे इस महत्त्वपूर्ण नीति को धरातल पर नहीं उतारा जा सक रहा है। उद्यमियों ने अब तक इस योजना पर अपने लाखों रूपये भी डुबा दिये मगर बैंकों द्वारा अनावश्यक परेशान किये जाने से वै निरास है।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

बाहर से आने वाली बसों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य

रोडवेज की बसों में कुरियर सेवा की जा सकती है आरंभ

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही को लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार पंजीकरण और कोविड टेस्ट नियम को लागू किया था, लेकिन भारी विवाद के बाद फिलहाल किसी टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जबकि पंजीकरण कराने की अनिवार्यता को बाहर बसों के लिए अब भी रखा गया है। इतना ही नहीं, मौजूदा कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल एक तय संख्या में ही अन्य राज्यों की बसों को उत्तराखंड आने की अनुमति दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड परिवहन निगम अंतरराज्यीय बस सेवा खुलने के बाद लगभग 350 से अधिक अपनी बसों को प्रतिदिन दूसरे राज्यों में संचालन के लिए भेज सकता है।

इतना ही नहीं, लंबे समय से चल रहे घाटे की आपूर्ति को कुछ हद तक पूरा करने के चलते रोडवेज की बसों में कुरियर सेवा भी आरंभ की जा सकती है। इसके लिए बाकायदा संबंधित कंपनियों से वार्ता चल रही है।